राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 1 ■ अंक 9 ■ फरवरी 2018 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 40

राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के 52 वर्ष

WHY WE NEED SIMULTANEOUS ELECTIONS ? 10

भीमा कोरेगांव का सच 25

राष्ट्र निर्माण में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की समृद्ध परंपरा का वाहक इसरो 28

परिषद् गतिविधियां

पोर्टब्लेटर (अंडमान – निकोबार) में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 'स्वच्छ भारत – नवीन भारत' मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना करते पद्म श्री नरेश चन्द्र लाल व अभाविप पदाधिकारी

अभाविप के प्रकल्प 'जिज्ञासा' द्वारा कोलकाता में आयोजित संगोष्ठी के दौरान मंचासीन अतिथि एंव अभाविप पदाधिकारी

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 1, अंक 9
फरवरी, 2018

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रित।

इस अंक में

05 **अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन (सील): राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के 52 वर्ष**
भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक संपदा तथा सांस्कृतिक वैभव...

संपादकीय	04
WHY WE NEED SIMULTANEOUS ELECTIONS ?	10
स्वामी जी के बताये मार्ग पर चले युवा : पद्म श्री नरेश चन्द्र लाल	14
राष्ट्रीय कला मंच ने आयोजित किये "मदारी" कला महोत्सव	16
भीमा कोरेगांव का सच	25
विनोबा भावे विश्वविद्यालय में लगातार तीसरी बार अभाविप की जीत	27
राष्ट्र निर्माण में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की समृद्ध परंपरा का वाहक इसरो	28
केरल में अभाविप कार्यकर्ता की हत्या	31
Bharat's Foreign Policy: Ambition and Transition	32
विचारक दीनदयाल जी	36
अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद प्रकाश नंदा को मिला पद्म भूषण पुरस्कार	38

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् एक अद्वितीय छात्र संगठन है जिसने एक अनूठी कार्यशैली विकसित की है। अपने जीवन का अमूल्य समय राष्ट्र कार्य में समर्पित कर ध्येय पूर्ण जीवन जीने वाले कार्यकर्ताओं की अटूट श्रंखला इस पद्धति में से निकली है।

कहा जाता है कि परिषद् स्थायी प्रकृति का प्रवाहमान संगठन है। कार्यकर्ता आते है, अपना योगदान देते हैं और चले जाते है। न अपने योगदान का अहंकार और न ही इसके बदले कुछ पाने की अभीप्सा। मौन साधना का यह क्रम सात दशकों से जारी है।कार्यकर्ता को मिलता है केवल सार्थकता का भाव और गहरा आत्मविश्वास, जिसे पाने के बाद जगत की कोई चुनौती रोक नहीं सकती।

छात्रशक्ति की यात्रा में एक ऐसा ही भावुक पल आया जब पिछले दो दशकों से निरंतर छात्रशक्ति की रीढ़ की हड्डी के रूप में पीछे रह कर सबकुछ संभालने वाले कार्यकर्ता श्री श्रीरंग कुलकर्णी ने लगभग ढाई दशक के सुदीर्घ पूर्णकालिक जीवन के बाद अपने निजी जीवन की ओर प्रस्थान किया । इस यात्रा में खट्टे -मीठे अनुभव भी हैं और कठिन परिस्थितियों में भी समय पर अंक निकालने के लिये की जाने वाली जी-तोड़ कोशिश के मर्मस्पर्शी संस्मरण भी। बरसों-बरस बिना सुनिश्चित आर्थिक संसाधनों के केवल संकल्प के बल पर छात्रशक्ति को जिलाये रखने की गाथा है यह यात्रा । छात्रशक्ति परिवार उनके सुखद भविष्य और सार्थक जीवन की मंगल कामना करता है।

वर्तमान सरकार के अंतिम बजट के साथ ही देश चुनावी वातावरण में आ पहुंचा है। लगभग सभी विधानसभा चुनावों में हाशिए पर पहुंच गये विपक्ष को राजस्थान उपचुनाव के परिणाम से राजनीतिक संजीवनी मिली है। निःसंदेह आगामी लोकसभा चुनाव बड़े राजनैतिक परिणाम लेकर आयेंगे । विपक्ष इसके लिये कुछ भी कसर न उठा रखेगा। पिछले दिनों आरोप-प्रत्यारोप का जो गंदलापन देखने को मिला, और राजनैतिक बढ़त के लिये साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने की जो कोशिशें सामने आयीं उनमें और बढ़ोतरी की संभावना है। कासगंज जैसी घटनाओं का सबक यही है कि हम किसी उकसावे में न आयेंगे और राजनीतिक षड्यंत्र में फंसने से बचें।

गत माह में अनेक प्रान्तों के अधिवेशन सम्पन्न हुए तथा पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण इस अंक में संकलित है। सूचनाप्रद लेखों और स्थायी स्तंभों के साथ फरवरी अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है।

होली की हार्दिक शुभकामना सहित,

आपका

संपादक

अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन (सील) : राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के 52 वर्ष

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक संपदा तथा सांस्कृतिक वैभव का मनोरम स्थल है, यहां की प्राकृतिक छटा किसी को भी लुभा सकती है। यहां पर प्राकृतिक संपदा एवं सास्कृतिक भव्यता का असीम भंडार हैं, जो सम्पूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दुर्लभ है। इस छोटे से क्षेत्र में 220 से अधिक जाति (166 से अधिक जनजातियों) के लोग निवास करते हैं और इनकी जितनी जातियां हैं उतनी ही भाषाएं हैं फिर भी सभी एक संस्कृति से जुड़े हैं। लोग कहते हैं कि पूर्वोत्तर में प्रकृति ने पूरा खजाना ही बिखेर दिया है। इस क्षेत्र में 51 प्रकार के वन और 15,000 से अधिक विभिन्न वनस्पतियों की जातियां पायी जाती है। नदियों, पहाड़ों, झरनों से भरा पूर्वोत्तर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के लिए तो यह भारतीय संस्कृति का मुख्य द्वार है। यहां के विभिन्न समुदायो की अनेक भाषाएं, खुबसूरती और उनकी परंपराएं 'विविधता में एकता' की अनूठी मिसाल पेश करती है।

।अजीत कुमार सिंह।

राष्ट्रीय एकात्मता को स्थापित करने एवं विविधता में एकता का मूल मंत्र को लिए हुए 1966 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के द्वारा देश के पूर्वोत्तर राज्यों के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'अन्तर राज्य छात्र जीवन दर्शन' के नाम से अभिनव प्रकल्प का प्रारंभ किया गया । 1962 के युद्ध में चीन द्वारा देश के पूर्वोत्तर भाग में अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्ज़ा कर लेने के बाद न केवल पूर्वोत्तर की तरफ सबका ध्यान गया बल्कि यह बात भी ध्यान में आई कि देश का अहम् हिस्सा होने के बाद भी पूर्वोत्तर कटा हुआ सा प्रतीत होता है और वहां के लोग अपनी बोली, पहनावा, रहन - सहन की वजह से खुद को देश की बाकी हिस्से से अलग - थलग महसूस कर रहे हैं। इन्ही सबको ध्यान में रखते हुए अभाविप ने जागरूकता, एकात्मता एवं स्वालंबन के तीन सूत्रीय लक्ष्य को लेकर पूरे देश में हर वर्ष सील

(SEIL) यात्रा निकाली जाती है। 1966 से लेकर आज तक अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन 'सील' के तहत सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में परस्पर आपसी संवाद को बढाकर पूर्वोत्तर के युवाओं को देश के शेष भागों को जानने तथा शेष भाग के युवाओं को भी पूर्वोत्तर को जानने के लिए मौका प्रदान करती है, ताकि राष्ट्रीय एकता और एकात्मता की भावना को देश के शेष भागों में जाकर समझे, साथ ही देश के लोग पूर्वोत्तर के भागों को समझने का प्रयास करें।

इस यात्रा के तहत सील प्रतिभागी विभिन्न परिवारों में ठहरते हैं तथा परिवार के सदस्यों के साथ रह कर वहां की रीति - नीति, सांस्कृतिक - भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक परिस्थितिओं से रूबरू होते हैं। इस अनोखी यात्रा के दौरान प्रतिभागी न केवल राष्ट्रीय एकात्मता के बंधन में बंध जाते हैं बल्कि उस परिवार के साथ आत्मीय संबंध स्थापित हो जाते है। इसी प्रकार शेष भारत से भी प्रतिभागी पूर्वोत्तर जाकर वहां की समस्याओं, संस्कृति , वेश-भूषा, रहन - सहन, खान - पान, प्राकृतिक संसाधनों, परिस्थितियों आदि का अध्ययन करते हैं साथ ही पूर्वोत्तर के जनजातीय परिवारों में रूक कर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से पूर्वोत्तर एवं शेष भारत के लोगों के बीच आत्मीय संबंध स्थापित होती है।

'सील' के द्वारा वर्ष 2018 की राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा तीन जनवरी को गुवाहाटी में परिचय वर्ग के साथ शुरू हुआ, जो देश के नौ राज्यों के 15 शहरों कटक, हैदराबाद, हुबली, दावणगिरे, चित्रदुर्ग, तुम्कुरू, कोल्हापुर, पनवेल, मुंबई, सूरत, कोटा, गुरूग्राम, नई दिल्ली एवं पटना होते हुए वापस गुवाहाटी में जाकर समाप्त हुआ। सील यात्रा के संयोजक बालकृष्ण बताते हैं कि इस यात्रा में पूर्वोत्तर के सातों राज्यों से 19 जिलों की 21 जनजातियों से कुल 60 प्रतिभागी शामिल हुए जिसमें 22 छात्राएं, 36 छात्र एवं तीन संयोजक शामिल हैं। ये सभी प्रतिनिधि देश भर के 179 मेजबान परिवारों में रहकर भारत का प्रत्यक्ष दर्शन किया। यात्रा को दो गटों में बांटा गया था। पहला गट चार जनवरी को कटक, हैदराबाद, दांवगिरी, कोल्हापुर, मुंबई होकर गुवाहाटी पहुंचा। वहीं दूसरा गट चार जनवरी को ही गुवाहाटी से निकलकर सूरत, कोटा, गुरूग्राम, नई दिल्ली, पटना होते हुए वापस गुवाहाटी पहुंचा। श्री बालकृष्ण के मुताबिक यात्रा देश के दस विश्वविद्यालय, 16 महाविद्यालय, इंजनियरिंग महाविद्यालय एवं अन्य केन्द्रों/कारखानाओं में गई, जहां लगभग बीस हजारों छात्रों के द्वारा प्रतिनिधियों को स्वागत किया गया। वहीं कई स्थानों पर सार्वजनिक अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया है, जिसमें समाज के हजारों लोगों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान हरियाणा के गुरूग्राम में केन्द्रीय मंत्री जीतेन्द्र सिंह, कोल्हापुर(महाराष्ट्र) में मंत्री दादा भाई, पटना (बिहार) में उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने प्रतिनिधियों की अगुवानी की। यात्रा का समापन 23 जनवरी को गुवाहाटी के युवा विकास केन्द्र में अनुभव कथन वर्ग के साथ समाप्त हुआ, समापन समारोह में अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नीरव घेलानी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।

सील के माध्यम से राष्ट्रीय एकात्मता का अलख जगा रही है अभाविप – जितेन्द्र सिंह

गुरूग्राम में सील प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया गया, सील प्रतिनिधि 12 जनवरी को गुरूग्राम पहुंचे थे। प्रतिनिधि तीन दिनों तक गुरूग्राम में स्थानीय परिवार के यहां ठहरे हुए थे। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित थे। अपने संबोधन के दौरान मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर के छात्रों का देश के दूसरे राज्य में आकर वहां की लोक-संस्कृति को देखने, परखने और उस पर विचार करने का स्वर्णिम मौका देता है। साथ ही, पूर्वात्तर के छात्रों की भाषा, लोक-संस्कृति से देश के अन्य राज्यों के लोगों को भी जानने का मौका मिलता है।

इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात भले ही देश में सवाल के रूप में उठता रहा है लेकिन जो लोग पूर्वात्तर को जानते हैं वहां, कोई इस प्रश्न को उठाए, तो उसे लोग ताज्जुब से देखेंगे। पूर्वोत्तर में 'हाउस वाइफ' नहीं बल्कि 'हाउस हसबैंड' का शब्द प्रचलित है।

आत्मीयता का केन्द्रबिंदु है सील : विक्रांत खंडेलवाल

सील का दूसरा जत्था 19 जनवरी को मुंबई पहुंचा, वहां पर उनके सम्मान में अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें मुंबई के कई गणमान्य लोग उपस्थित

थे। अभाविप के विशेष क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल ने कहा कि "भारत एकात्मता यात्रा का आयोजन परिषद के प्रकल्प SEIL द्वारा गत 52 वर्षों से अनवरत आयोजित किया जाता रहा है। एक स्थानीय परिवार के साथ इन पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों का तीन दिन का साथ जीवन भर के रिश्ते निर्माण कर देता है, इन यात्रियों की विदाई के समय लगता है मानों घर से बेटी विदा हो रही है।

वहीं समाजसेवी और उद्योगपति विनोद भीमराजका ने पूर्वोत्तर से आये विद्यर्थियों को अपनी पूर्वोत्तर यात्रा और भावनात्मक संबंधों से जुड़ें अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि सील प्रतिनिधियों के साथ ये देश प्रेम का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़ कर लगता है, जब हर मेजबान शहर इन 3 दिनों में अपना पूरा स्नेह उन पर लूटा देना चाहता है। आज पूर्वात्तर भारत मे होने वाला सामाजिक राजनीतिक बदलाव इस प्रकार के सैंकड़ों प्रयासों , हजारो कार्यकर्ताओं की समय दान रूपी तपस्या का परिणाम के अलावा और क्या है ?

पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ने का अनोखा मंच है सील : पेमा खांडू

सील का जत्था 16 जनवरी को दिल्ली पहुंचा, जहां पर प्रतिनिधियों के लिए अभिनंदन समारोह आयोजित किये गये। अभिनंदन समारोह दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई थी। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू थे। पेमा खांडू ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्षों से उपेक्षित पूर्वोत्तर भारत की ओर इस सरकार के आने के बाद ध्यान देना शुरू हुआ परंतु विद्यार्थी परिषद् ने तो सन् 1965 से ही पूर्वोत्तर के विकास के लिए 'सील' जैसे प्रकल्पों के माध्यम से पूर्वोत्तर के लोगों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने का प्रयास लगातार करती आ रही है। उन्होंने कहा कि अभाविप के सील यात्रा से पूर्वोत्तर और शेष भारत के लोगों के बीच भावनात्मक रिश्ते कायम हुए हैं और राष्ट्रीय एकात्मता हेतु यह एक अद्भुत आयाम है। सील के चेयरमैन अतुल कुलकर्णी ने बताया कि सील 1965 से लगातार चला आ रहा अभाविप का एक ऐसा आयाम है जिसमें हर साल पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों का दो दल शेष भारत में जाते हैं, जहाँ वे मेजबान परिवार में रहते हैं और उस क्षेत्र से परिचित होते हैं। इसी प्रकार शेष भारत से भी एक दल पूर्वोत्तर के राज्यों में जाते हैं और अपने देश के एक विशिष्ट भाग से परिचित होते हैं। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किये। समारोह के दूसरे दिन प्रतिनिधियों को दिल्ली भ्रमण करवाया गया, भ्रमण के तहत प्रतिनिधियों ने इंडिया गेट, संसद भवन जैसे ऐतेहासिक धरोहरों का दर्शन किया। इसके पश्चात प्रतिनिधि केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह एवं केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से भी मिले, मंत्री द्वय ने प्रतिनिधियों को गले लगाया और स्वर्णिम भविष्य की शुभकामना दी साथ ही देश के विकास में युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया।

'अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश : सुशील मोदी

'अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन' के प्रतिनिधियों को पटना स्टेशन पहुंचते ही फूल - मालाओं से लाद दिये गये। प्रतिनिधियों के लिए अभाविप पटना की ओर से भी अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत की विशेषता एकरूपता में नहीं बल्कि अनेकता में एकता है। इसीलिए हम कहते हैं, 'अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पूर्वोत्तर के छात्र-छात्राएं देश के अन्य राज्यों में आकर भारतीयता व एकता के भाव को समझते हैं, उसी प्रकार अन्य राज्यों के लोगों को भी पूर्वोत्तर के राज्यों में जाकर वहां के प्राकृतिक-सांस्कृतिक सौंदर्य को देखना-समझना चाहिए।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एनआईटी पटना के निदेशक डॉ. पीके जैन ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से पूर्वोत्तर भारत का पूरे देश के साथ भावनात्मक रिश्ता स्थापित होगा। अध्यक्षता कर रहे डॉ. आर. एन. सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम देश को मजबूती प्रदान करेगा। वहीं अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन ने कहा कि जब-जब देश के सामने खतरा उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से अभाविप ने देश के युवाओं को जगाने का काम किया। अतिथियों का स्वागत पटना की महापौर सीता साहू ने किया। ■

क्या कहते हैं सील प्रतिभागी....

सील प्रतिनिधि के रूप में चयन होने के बाद मैं सोचने लगा कि मैं किसके साथ जाऊंगा, कैसे रहूंगा, मेरे साथ जो प्रतिनिधि जाने वाले हैं उन्हें मैं जानता तक नहीं...। चार जनवरी 2018 को गुवाहाटी से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई, यात्रा के दौरान भी मेरी चिंता यथावत थी, लेकिन सूरत पहुंचने के बाद मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। हमलोगों को किसी होटल में ठहराने के बजाय एक परिवार में ठहराया गया। मेजबान परिवार के घर पहुंचने के बाद आंटी ने मुझसे कहा कि दूर से आए हो, थकावट होगी, जाओ जाकर हाथ - पैर धो लो। मैं अपने गंदे कपड़े को बाहर ही रख दिया। मैं स्नान कर बाथरूम से बाहर निकला तो देखा कि आंटी मेरे गंदे कपड़े धो रही है। आंटी को कपड़े धोता देख मैं काफी भावुक हो गया। आंटी में मेरी मां की तस्वीर दिखाई देने लगी, इसके बाद मैं उन्हें मम्मी कह कर पुकारने लगा। उनके व्यवहार से मुझे लगा ही नहीं कि मैं घर के बाहर हूं। सूरत के बाद हमलोग कोटा पहुंचे, वहां पर मेरी मुलाकात देश के प्रसिद्ध संस्थान एलेन के निदेशक से हुई, उनसे मिलकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा था। कोटा के बाद गुरूग्राम में पहुंचा, वहां पर मुझे बोला गया कि सील यात्रा के अनुभव को मीडिया के साथ साझा करना है, मैंने रात भर तैयारी की, लेकिन पत्रकार वार्ता के दौरान मैं सब कुछ भूल गया और दिल की बात को मीडिया से साझा दिया। मीडिया से बात करने के दरम्यान मेरे आंखों में आंसू आ गये। मैं सील यात्रा को जीवन में कभी नहीं भूल सकता।

— सनबोरिकी बायम, *मेघालय*

यह पल मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पल है। सील यात्रा के माध्यम से मैंने अनजान मित्रों के साथ दर्जनों शहर का भ्रमण किया और अब ये मेरे अच्छे मित्र बन गये। इसके पहले भी मैंने कई यात्रा की है परंतु सील यात्रा अनोखी है। गुवाहाटी से शुरू होकर, सूरत, कोटा, गुरूग्राम, नई दिल्ली और पटना गया। इस दौरान मैं जिस परिवार में रूका उस परिवार के लोगों ने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार किया। इससे पहले जब मैं "अलग भाषा - अलग वेश, फिर भी अपना एक देश" सुनता था तो समझ नहीं आता था, लेकिन सील यात्रा के बाद के बात उक्त पंक्ति का अर्थ समझ में आया।

— आर. के. नरेश - *मणिपुर*

मैं पहली बार अपनी घर से बाहर निकला हूं, सील यात्रा में आकर रोमांचित महसूस कर रहा हूं। सील यात्रा के दौरान बिताये गये एक एक पल मेरे लिए महत्त्वपूर्ण है। यात्रा के दौरान मुझे लगता था कि मैं जहां जा रहा हूं, वहां के लोग मेरी भाषा समझेंगे कि नहीं, मैं अपनी बातों को उन्हें कैसे समझा पाऊंगा लेकिन पूरी यात्रा के दौरान मुझे कभी भाषागत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मेरी जरूरत के सामान वहां पहले से मौजूद रहते थे। सील यात्रा के लिए जब मेरा चयन हुआ तो मुझे लगता था कि होटल में ठहराया जायेगा और पर्यटन कराया जायेगा, लेकिन यात्रा के दौरान मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मुझे स्थानीय परिवार में ठहराया गया, रात्रि विश्राम भी उनके साथ ही होता था। इस मौके पर मैंने कई ऐतेहासिक स्थलों का भी दर्शन किया, दिल्ली में इंडिया गेट देखा, भारत के गृह मंत्री ने हमें गले लगाया, जिसे मैं टेलीविजन और अखबार में देखता था उसे साक्षात देखकर लग रहा था मानों स्वपन देख रहा हूं।

— ब्रिटिश रिंग - *त्रिपुरा*

मैं सर्वप्रथम सील यात्रा के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमलोगों को देश को जानने का मौका दिया। सील यात्रा के दरम्यान सूरत, कोटा, गुरूग्राम, दिल्ली और पटना में सम्मान और अपनापन को पाकर भावुक हूं। मेरे जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ अनुभव है, मैंने पहली बार एक साथ इतने प्रदेश का भ्रमण किया, इससे पहले मैं इन शहरों का नाम समाचार पत्रों एवं मानचित्रों में देखा और पढ़ा था। अलग - अलग राज्यों के अलग - अलग खान पान और संस्कृति को देखकर मैं अभिभूत हूं। किसी चीज की जरूरत होती थी तो हम इशारों से बात करते थे और आश्चर्य की बात है कि मेजबान परिवार उसे समझ लेते थे और मेरी परेशानी को दूर करते थे। अभाविप के द्वारा सील यात्रा के आयोजन को हम, सभी पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए वरदान हैं।

— सेवेतो डोजो - *नागालैंड*

मिजोरम के बाहर मेरी पहली यात्रा है, इससे पहले मैं कभी मिजोरम से बाहर नहीं गया। यात्रा के दौरान मुझे काफी कुछ नया देखने को मिला, कई नये मित्र बने। एक नया परिवार मिला जिनके साथ हमने कई दिन बिताया, उनके रहन सहन को जानने को मिला। जब मैं इन परिवार से विदा ले रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं अपने परिवार से सदा के लिए बिछुड़ रहा हूं। इनलोगों ने मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार दिया, अनेक प्रकार के पकवान खिलाये। सील यात्रा में आने के बाद मुझे "विविधता में एकता - भारत की विशेषता" का मूल स्वरूप देखने को मिला।

— आईसाक लालरिंनघेटा - *मिजोरम*

सील के माध्यम से मैं सूरत, कोटा, गुरूग्राम, दिल्ली, और पटना गई। यह यात्रा मेरे जीवन की स्वर्णिम यात्रा है, इस यात्रा की यादों को मैं जीवन भर सहेज कर रखूंगी। सूरत में अनेकों उद्योग के कारखानें देखे, कोटा में अनेकों शैक्षणिक संस्थान एवं ऐतेहासिक इमारतों को देखी, दिल्ली में हमलोगों के लिए अभिनंदन समारोह रखा गया था, अभिनंदन समारोह के बाद हमलोगों को घुमाने ले जाया गया, जहां पर हमने इंडिया गेट, विजय चौक इत्यादि देखा। सील यात्रा के दौरान में जिस मेजबान परिवार के यहां रूकी उनलोगों ने मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार दिया। यहां आने के बाद पता चला कि मेरा एक परिवार है, जो हमारे लिए फिक्रमंद है।

— डामपिलु मीनिन - *अरूणाचल प्रदेश*

मेरी यात्रा गुवाहाटी से तीन जनवरी को शुरू हुई, गुवाहाटी से मैं वाया हावड़ा सूरत पहुंचा। सूरत की साफ - सफाई को देखकर मैं काफी आश्चर्यचकित हुआ। सूरत में मेजबान परिवारों ने मुझे अपने संतान की तरह प्यार दिया। सूरत के बाद हमलोगे कोटा गये, कोटा के ऐतेहासिक महलों का दीदार किया। मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी करवाने वाले एलेन, रिजोनेन्स के चेयरमेन से मुलाकात हुई, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। कोटा के बाद गुरूग्राम पहुंचा, गुरूग्राम से अपने सपनों का शहर दिल्ली पहुंचा। यहां मैं पहली बार मेट्रो की सवारी की, मेट्रो की सवारी मेरे लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। दिल्ली में हमलोगों ने संसद भवन, इंडिया गेट आदि जगहों का भी भ्रमण किया। दिल्ली के बाद हमलोग पटना पहुंचे, पटना में हमलोगों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। मैं यह सब देखकर रोमांचित हो रहा था, घर से निकले दो सप्ताह से अधिक हो चुके थे, लेकिन लग रहा था मानों आज ही आया हूं। सूरत, कोटा, गुरूग्राम, दिल्ली, पटना आदि सभी जगहों पर मेजबान परिवारों ने मुझे काफी प्यार और सम्मान दिया, यह यात्रा मेरे जीवन का सबसे खास यात्रा है।

— आकाश ब्रह्मा - *असम*

Why We Need Simultaneous Elections ?

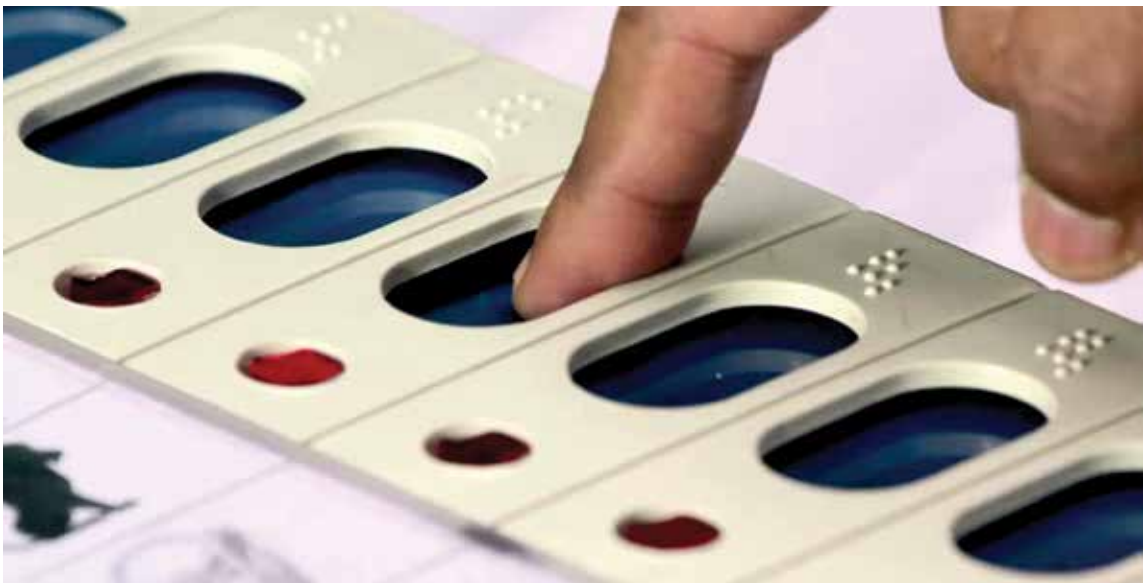

Swadesh Singh

The kind of electoral exercise that we witness in India is unparalleled in the world. Due to the sheer size of electorate and the expanse of our democracy, this electoral exercise doesn't only assume gigantic proportions, it also leads to huge electoral expenditure. To add to the existing woes, our general and state elections are not held simultaneously and thereby one part or the other of our country is always electorally alert. The Election Commission of India is on its foot throughout the year because of this. This is the situation when we are not taking account of local elections for Panchayat and urban municipalities. The ever-rising electoral expenditure on the country because of this can prove detrimental to our governance and developmental goals. Simultaneous elections have been mooted out by many as a remedy to this problem of Indian democracy.

History of Indian Elections

The first election after Independence was held simultaneously for Parliament and State Assemblies in 1952. The practice was followed without any hitch in three subsequent elections held in 1957, 1962, and 1967. This was mainly because non-Congress regional parties were not as powerful and influential as Congress and thereby were not in a position to dislodge it in the legislatures or in general elections. Things after 1967 changed. It was on account of both state and national politics due to which elections to parliament and state assemblies were delinked. The Fifth General Elections were due in 1972. But in early 1971 Indira Gandhi dissolved the Lok Sabha, and held the Fifth Lok Sabha elections in March 1971. The Assembly elections took place as scheduled in 1972. This is how the initial delinking of Lok Sabha and Assembly elections took place. Due to irresponsible and politically motivated use of article 356 by Indira Gandhi

government, many state assemblies were dissolved in between leading to finalization of this delinking process. Thereafter, emergence of regional parties in some States altered the political climate effectively and led to perpetual instability of elected State governments. It forced mid-term elections in many States thus delinking elections to Legislative Assemblies and the Lok Sabha was almost finalised. Today, simultaneous elections have become exceptions rather than the rule. As a result, the Election Commission is busy throughout the year conducting polls in some part of the country or other.

Rising Expenditure

2014 elections were the most expensive Lok Sabha elections ever, entailing a cost of Rs.3,426 crore to the national exchequer, a substantial jump of 131% over the Rs.1,483 crore incurred in the 2009 polls. The official expenses are part of the whopping Rs.30,000 crore projected to be spent by the government, political parties and candidates in the nine-phased polls. Voter awareness campaigns, distribution of voter slips ahead of the election date, and use of the voter verified paper audit trail for the first time in these polls pushed the expenditure further. In 1952, the cost of elections per elector was 60 paise which increased to Rs 12 per elector in 2009, a 20-fold hike. With the size of electorate rising and the burden on a candidate or political party to expand its reach to this increasing electorate, we will witness even more rising costs of the election.

The funds collected by the political parties also show a significant rise. The EC report indicates that funds collected by the national political parties increased by a whopping 418 per cent in the past 10 years. It is an open secret as to what form of political corruption takes place in fund collection by various parties. To add to the woes, the cash component of the funds collected forms a major part as compared to the donations made by cheques and drafts.

The funds collected by the political parties also show a significant rise. The EC report indicates that funds collected by the national political parties increased by a whopping 418 per cent in the past 10 years. It is an open secret as to what form of political corruption takes place in fund collection by various parties. To add to the woes, the cash component of the funds collected forms a major part as compared to the donations made by cheques and drafts.

Some of the other pertinent issues arising out of delinking of elections are discussed further.

Policy Paralysis

Under the model code of conduct (MCC), governments cannot do anything which may have the effect of influencing voters in favour of the party in power, and political parties and candidates are forbidden from indulging in any corrupt practices. Grants, new schemes / projects cannot be announced. Even the schemes that may have been announced before the MCC came into force, but that has not actually taken off in terms of implementation on field are also required to be put on hold.

Due to these stringent guidelines which comes into effect for 45 days after the schedule for elections are announced by the EC, the whole country (during the times of general elections) and states (during elections to state assemblies) come to a virtual standstill. The normal functioning of the government is hampered. It leads a situation of policy paralysis. It has become a model for inaction. Designed to prevent pre-poll populism by governments and political parties, the frequency of its application has turned the Election Commission's model code of conduct into a charter for non-governance.

The frequency of elections that we conduct makes the occurrence of such policy paralysis very regular. This is too high a price that we pay to sustain our democratic practices. It would be in the interest of nation if elections to Parliament and state assemblies are held simultaneously and model code of conduct is applied only once in five years.

Instability

Connected to the above issue, the delinking of elections also leads to a situation where we witness instability at the national level. When elections happen, it involves the whole machinery of government. The party in power cannot afford to look away and even the ministers of highest ranks get involved in the campaign process. This leads to hampering of normal functioning of government and negatively affects the governance of the country.

Lack of bold decision–making

If a party which is in power at centre loses election in a state, it is projected by the opposition as the results have made severe dent on its mandate to rule. This also leads to loss of confidence in the ruling regime. A negative atmosphere is created which contributes in the affecting the governance of country in an adverse way. A loss in a state election in the middle of the tenure of a government at national level is rapidly projected as a loss of credibility and hence all efforts are made by the strengthened opposition to stall any new reform measures.

Security issues

When the elections are announced, there is also a huge expense that has to be incurred by the government to ensure free and fair elections. For example, the exchequer was supposed to spend Rs 7000 to Rs 8000 crore to hold the electoral exercise for the 16th Lok Sabha. While the Election Commission was likely to spend around Rs 3,500 crore, the Union Home Ministry, Indian Railways, various other government agencies and state governments were to spend a similar amount to put in place means to ensure free and fair polls.

Fearing outbreaks of attacks by Maoist guerillas, terrorist violence and communal clashes between Hindus and Muslims, the Ministry of Home Affairs in 2014 mobilized some 200,000 security personnel – comprising 175,000 paramilitary forces and 25,000 state police officers -- across the country to protect polling stations and safeguard election results. In the last general election in 2009, the central government-provided security deployment consisted of 120,000 personnel. These figures do not include the hundreds of thousands of other provincial police and local security forces that were deployed to polling stations across the country. This added feature makes our elections more expensive and the fierce competition in elections may also lead to loss of lives at many places.

Recommendations

In the first annual report of the Election Commission submitted in 1983, the then chief election commissioner R.K. Trivedi had observed: "The commission is of the view that a stage has come for evolving a system by convention, if it is not possible or feasible to bring about a legislation, under which the general elections to the House of the People and legislative assemblies of the states are held simultaneously."

170th report of Law Commission of India on 'Reform of the Electoral Laws', 1999 mentioned in this regard the following, 'This cycle of elections every year, and in the out

of season, should be put an end to. We must go back to the situation where the elections to Lok Sabha and all the Legislative Assemblies are held at once. It is true that we cannot conceive or provide for all the situations and eventualities that may arise whether on account of the use of article 356 or for other reasons, yet the holding of a separate election to a Legislative Assembly should be an exception and not the rule. The rule ought to be one election once in five years for Lok Sabha and all the Legislative Assemblies'.

The Law Commission of India in its report of 1999 has dealt with the problem of premature and frequent elections. It had recommended an amendment of this rule on the lines of the German Constitution, which provides that the leader of the party who wants to replace the chancellor has to move the no-confidence motion along with the confidence motion. If the motions succeed, the president appoints him as the chancellor.

170th report of Law Commission of India on 'Reform of the Electoral Laws', 1999 mentioned in this regard the following, 'This cycle of elections every year, and in the out of season, should be put an end to. We must go back to the situation where the elections to Lok Sabha and all the Legislative Assemblies are held at once.

One of the reform proposals mentioned in National Commission to Review the Working of Constitution is: "Hold State level and parliamentary level elections at the same time. This would reduce election expenditure."

The Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice is reported to be mulling over the option. It has also sought the opinion of the intelligentsia for impartial views and of various stakeholders impacted by elections to legislative bodies. The parliamentary committee headed by EMS Natchiappan and has initiated the process of examining the possibility of holding Lok Sabha and Assembly elections together, a practice which had ended in 1967. The committee submitted its report on the Feasibility of Holding Simultaneous Elections to Lok Sabha and Legislative Assemblies. The Committee noted that the holding of simultaneous elections to Lok Sabha and state assemblies would reduce: (i) the massive expenditure that is currently incurred for the conduct of separate elections; (ii) the policy paralysis that results from the imposition of the Model Code of Conduct during election time; and (iii) impact on delivery of essential services and (iv) burden on crucial manpower that is deployed during election time.

Many times, Prime Minister Narendra Modi have supported this idea of having simultaneous elections for the Lok Sabha and state assemblies. President Pranab Mukherjee, during his lecture to school students on the Teachers' Day had endorsed the idea of holding simultaneous Lok Sabha and state legislative assemblies' elections. President Mukherjee had said that with some election or other throughout the year, normal activities of the government come to a standstill because of the model code of conduct. "This is an idea the political leadership should think of. If political parties collectively think, we can change it", he had said.

India being a developing country cannot ill afford to bear the huge expenditure involved in electoral exercise. From the above discussion it is evident that the issues that we are facing now in terms of spiralling costs of elections, administrative burden on government and EC and governance deficit resulting from these can be better resolved if we revert back to our earlier electoral system whereby we had simultaneous elections for both parliament and state assemblies. ■

(Author is Assistant Professor in Satyawati College, Delhi University)

स्वामी जी के बताये मार्ग पर चले युवा : पद्म श्री नरेश चन्द्र लाल

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने स्वामी विवेकानंद की 155 वीं जयंती (राष्ट्रीय युवा दिवस) पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर अभाविप द्वारा देश के विभिन्न भागों में विवेकानंद संदेश यात्रा, शोभायात्रा, संगोष्ठी, वाहन - रैली, छात्रसभा, रक्तदान शिविर, नशामुक्ति शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण - प्रतियोगिता, साहित्य वितरण, मैराथन दौड़ आदि कार्यक्रम आयोजित किये गये। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी परिषद् ने कार्यकर्ताओं में विवेकानंद के जीवन चरित्र को रेखांकित कर उनके सपनों का भारत बनाने बनाने का संकल्प लिया।

अभाविप **पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार)** की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर "नवीन भारत - स्वच्छ भारत" मैराथन दौड़ आयोजित की गई, जिसमें 250 से अधिक छात्र - छात्राओं ने भाग लिया। यह मैराथन पोर्टब्लेयर स्थित विवेकानंद केन्द्र से शुरू होकर जेएनआरएम पर जाकर समाप्त हुआ। मैराथन के बाद संगोष्ठी के दौरान मुख्य अतिथि पद्म श्री नरेश चंद्र लाल ने कहा कि विवेकानंद करोडों युवाओं के आदर्श हैं, विवेकानंद के बताये मार्ग का अनुसरण करने से भारत पुनः विश्व गुरू बन सकता है। विद्यार्थी परिषद् द्वारा "नवीन भारत - स्वच्छ भारत" मैराथन में युवाओं का उत्साह देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानों मैं पुनः अपने किशोरावस्था में लौट चुका हूं। अभाविप के कार्यकर्ता बेहद अनुशासित एवं सुसंस्कृत हैं। वहीं मैराथन के संयोजक प्रदीप चक्रवर्ती ने कहा कि विद्यार्थी परिषद् राष्ट्रभक्त युवाओं का संगठन है, जो हमेशा राष्ट्र के पुर्नवैभव को स्थापित के लिए कृतसंकल्प है। मौके पर अभाविप विभाग प्रमुख डॉ. कन्डीमुथु, विवेकानंद केन्द्र के सचिव ए. राधाकृष्णन, प्रदेश अध्यक्ष अंजनी कुमार श्रीवास्तव, प्रदेश मंत्री डी. श्रीकांत राव सहित सैंकड़ो अभाविप कार्यकर्ता मौजूद थे।

स्वामी विवेकानंद जयंती को **मध्यभारत** के 34 जिलों में धुमधाम से मनाया गया। प्रदेश मंत्री बंटी चौहान नें कहा कि हर युवा को कहीं न कहीं समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए, लंबी आयु जीना आवश्यक नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने 39 वर्ष की आयु में ही विश्व में डंका बजा दिया था। स्वामी जी ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि आज अभाविप ने प्रांत के सभी जिलों के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में वाहन रैली, संगोष्ठी, मंचीय कार्यक्रम, शोभायात्रा, वृक्षारोपण एवं संदेश यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें ग्वालियर में 2142, नीमच 1710, मंदसौर 1709, गुना 1077 समेत प्रांत के 34 जिलों में छात्र-छात्राओं ने भागीदारी ली।

अयोध्या (अवध) में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की की ओर से साकेत महाविद्यालय के जगदंबिका प्रताप नारायण सभागार में स्वामी विवेकानंद जयंती सप्ताह के मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा, मुख्य वक्ता डॉ. देवानंद तिवारी, विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय थे।

गोष्ठी की शुरुआत मां सरस्वती व विवेकानंद के चित्र के सामने दीप प्रज्ज्वलित करने के साथ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि सुरेश राणा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणादायी साहित्य के समान है। भारतीय इतिहास में अनेकों युवाओं ने देश की आजादी के लिए जान की बाजी लगा दी। विद्यार्थी परिषद ने ऐसे ही युवाओं के मन में राष्ट्रभक्ति की अलख को जगाकर देश समाज के कार्य किया है। उन्होंने विद्यार्थी परिषद् को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जिस प्रकार भारतीय सैनिक विभिन्न परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के अंदर व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध सदैव आवाज उठती है।

वहीं डॉ. देवानंद तिवारी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों में भारतीय संस्कृति की रक्षा व प्रसार का संदेश है, जबकि महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने उपस्थित छात्रों को स्वामी विवेकानंद के बताए गए रास्ते पर चलने

की सीख दी। उन्होंने कहा शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने मात्र संबोधन भर से भारतीय संस्कृति की शक्ति को वैश्विक फलक पर रखा। प्राचार्य डॉ. प्रदीप खरे ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

वहीं अभाविप **दुमका (झारखंड)** की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इंडोर स्टेडियम में सम्मान समारोह का आयोजन कर विगत दिनों से करायी गई प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीतों से हुई। इसके बाद बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। इसके बाद एक-एक कर विजेताओं को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया।

अभाविप के केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य सुजीत वर्मा ने कहा कि विवेकानंद जी से सभी को सीख लेने की जरूरत है। अभाविप उनके बताए हुए रास्तों पर चल रही है। हर किसी को उनकी कार्यशैली से प्रेरणा लेकर देश के लिए कुछ करने की आवश्यकता है।

फरीदाबाद (हरियाणा) के शिव विहार स्थित बीके वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में अभाविप ने स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती व स्वामी विवेकानंद को श्रद्धासुमन पुष्प अर्पित करके की। जिसमें मुख्य अतिथि अभाविप के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप भारद्वाज रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य सतीश कौशिश ने की व मंच संचालन अर्जुन शास्त्री ने किया।

अभाविप के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप भारद्वाज ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की ओर से 12 जनवरी से 23 जनवरी तक युवा सप्ताह मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की थी। उन्हीं के कारण विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बजा। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं नें भी अपने विचार रखे। प्राचार्य सतीश कौशिश ने बताया कि विवेकानंद के कथन मुख्य प्रेरणा देने वाले हैं, जिनसे करोड़ों लोगों का भविष्य बदला है और बदल रहा है। जिनमें मुख्य रूप से उठो, जागो, संघर्ष करो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कार्यक्रम के समापन पर स्कूल के प्राचार्य ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंटकर आभार प्रकट किया।

अभाविप **चम्पावत (उत्तरांचल)** के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद का 155वां जन्म दिवस, 'युवा दिवस' के रूप में मनाया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर मिष्ठान वितरित किया गया। कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी के बताए मार्ग में चलने का संकल्प लिया।

अभाविप **दिल्ली** के द्वारा रक्तदान एवं सगोष्ठी का आयोजन किया गया। दिल्ली के लाजपत नगर स्थित पीजीडीएवी महाविद्यालय में अभाविप के संगोष्ठी को संबोधित करते हुए परिषद् के ममता त्रिपाठी ने कहा कि विवेकानंद का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, भारत को उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए आज भी प्रासंगिक है। आज आवश्यकता है कि हमारे युवा इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने - अपने क्षेत्र में कार्य करें। कार्यक्रम में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रो. अवनिजेश अवस्थी ने युवाओं का आह्वान करते हुये कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाषचंद्र बोस तथा अन्य अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष के परिणामस्वरूप जो स्वतंत्रता मिली है उसे हम बरकरार रखे। यदि आज भारत माता की जय और 'वन्दे मातरम्' जैसे उद्घोषों पर कोई राष्ट्रविरोधी तत्व प्रश्नचिह्न लगाता है तो हम उसका कड़ा प्रत्युत्तर दें। हम अपने पूर्वजों के योगदान का स्मरण रखें और राष्ट्रविरोधी तत्वों के करतूतों पर मौन न रहें। वहीं अभाविप के प्रांत संगठन मंत्री अजय ठाकुर ने दयाल सिंह महाविद्यालय में युवाओं को स्वामी जी के पदचिह्नों पर चलने का आह्वान किया।

अभाविप **रोहतास (बिहार)** ने स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह का आयोजन कर उनके पद चिह्नों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंद वर्मा ने स्वामी विवेकानन्द के तैलचित्र पर दीप प्रज्ज्वलित और पुष्पांजलि कर किया। शिक्षा मंत्री कहा कि पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान व उपदेश से लोगों को चमत्कृत कर दिया। आज यह देश उनके आदर्शों पर चलने को तैयार हो रहा है। उनके आदर्श को युवा वर्ग को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि हर देश का युवा एक दिन विवेकानंद बन सकता है। हमारा देश आध्यात्मिक गुरुओं के नाम से जाना जाता है। वहीं पटना सांइस कॉलेज, पटना कॉलेज पटना, ए.एन.कॉलेज, आर.के.डी. कॉलेज, बी.डी.कॉलेज के अभाविप कार्यकर्ताओं द्वारा संगोष्ठी एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रांत संगठन मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ओजस्वी भाषण से पूरे विश्व को चकित कर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्वामी जी के पद चिह्नों पर चलने का आह्वान किया। ■

राष्ट्रीय कला मंच ने आयोजित किये "मदारी" कला महोत्सव

अभाविप के प्रकल्प 'राष्ट्रीय कला मंच' के द्वारा मदारी कला महोत्सव 23 से 25 जनवरी 2018 को दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के प्रांगण में आयोजित किया गया। मदारी के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय कला मंच के संयोजक सौरभ उनियाल ने कहा कि यह मदारी का दूसरा संस्करण है। गत वर्ष भी इस तरह के आयोजन किये गये थे। उन्होंने कहा इस वर्ष कुल 85 आवेदन आये, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, एमेटि विश्वविद्यालय, आंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ़ ओपन लर्निंग के साथ साथ स्वसंचालित संस्थाओं ने इसमें प्रतिभाग करने के लिए आवेदन किये। प्रथम चरण में संस्थान, संस्था एवं नाटकों के विषयों के आधार पर 52 संस्थाओं का चयन हुआ, दूसरे चरण में 52 संस्थाओं की स्क्रीप्ट को देखते हुए तीसरे और अंतिम चरण के लिए 36 संस्थाओं का चयन किया गया।

प्रतियोगिता में राजधानी कॉलेज की टीम को प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान लेडी श्रीराम कॉलेज को प्राप्त हुआ। टीम के साथ ही बेहतरीन अभिनय के लिए श्री अरबिन्दो कॉलेज के विनायक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का व्यक्तिगत स्तर पर पुरस्कार दिया गया। इस नुक्कड़ नाटक महोत्सव में दिल्ली में स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी 20 टीमों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने वृद्धों की परिवार में स्थिति, अंगदान, रक्तदान, महिलाओं से जुड़े मुद्दों आदि थीमों पर प्रस्तुतियां दीं, यह प्रतियोगिता दिल्ली विश्वविद्यालय में एक स्वस्थ प्रतियोगी वातावरण निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ स्क्रिप्ट के साथ समाधान देने में सफल रही, मदारी में रंगमंच और कला की दुनिया से जुड़े दो महत्वपूर्ण नाम सुमन वैद्य एवं अद्वैता काला निर्णायक की भूमिका में रहे। कार्यक्रम के समापन के मौके पर अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि " कला साधना का विषय है, इस प्रतियोगिता में ज्वलंत मुद्दों पर कलाकारों जिस अदभुत ढंग से प्रस्तुति दी, वह प्रशंसनीय है। मदारी के माध्यम से जो प्रस्तुतियां हुई उनके माध्यम से समस्याओं को समझकर उनके समाधान से बेहतर भारत निर्माण का सपना पूर्ण होगा।" अद्वैता काला ने सिनेमा एवं रंगमंच से जुड़े विभिन्न तथ्यों को छात्रों के समक्ष रखा एवं सभी प्रतियोगी छात्रो के उज्जवल भविष्य के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निर्धारण की बात कही।

वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रांत के कई नामचीन कवियों ने भाग लिया। इसी प्रकार 17 जनवरी को नोएडा में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में आगामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि 18 से 23 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव एवं मार्च में ही मुंबई में नेशनल फिल्म फेस्टीवल का आयोजन किया जायेगा। ■

प्रांतीय अधिवेशन

तेलगांना के 36 वें प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते अभाविप के राष्ट्रीय सह – संगठन मंत्री के. एन. रघुनंदन

तेलगांना प्रांतीय अधिवेशन के दौरान शोभा यात्रा निकालते अभाविप कार्यकर्ता

प्रांतीय अधिवेशन

अरूणाचल प्रदेश के पांचवें प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं मंचासीन अभाविप पदाधिकारी

अरूणाचल प्रदेश प्रांतीय अधिवेशन में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा

प्रांतीय अधिवेशन

पं. बंग के 35 वें प्रांतीय अधिवेशन का उदघाटन करते बंगला के प्रसिद्ध स्तम्भकार रंतिदेव सेन गुप्त एवं अभाविप अन्य पदाधिकारीगण

पं. बंग के प्रांतीय अधिवेशन में शोभायात्रा के दौरान अभाविप कार्यकर्ता

प्रांतीय अधिवेशन

छत्तीसगढ़ प्रांतीय अधिवेशन का दीप प्रज्ज्वलित कर उदघाटन करते केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर, साथ में हैं परिषद् के पदाधिकारीगण

खुले अधिवेशन के दौरान वंदे मातरम का उद्घोष करते अभाविप कार्यकर्ता

प्रांतीय अधिवेशन

मध्य भारत के स्वर्ण जयंती प्रांत अधिवेशन को संबोधित करते अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर व मंचासीन अभाविप के पदाधिकारी

मध्यभारत के प्रांतीय अधिवेशन के दौरान शोभायात्रा में अभाविप कार्यकर्ता

प्रांतीय अधिवेशन

मेरठ के प्रांतीय अधिवेशन के समापन समारोह के दौरान मंच पर अभाविप की नवनिर्वाचित टोली के साथ अभाविप पदाधिकारी

प्रांत अधिवेशन के दौरान ध्वजारोहण करते मेरठ प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश मंत्री

प्रांतीय अधिवेशन

जम्मू – कश्मीर के 53 वें प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते प्रदेश सह मंत्री जी. एम. अली

शोभायात्रा के दौरान जम्मू – कश्मीर के सड़को पर वंदे मादरम का उद्घोष

प्रांतीय अधिवेशन

दीप प्रज्ज्वलित कर अवध प्रांत के प्रांतीय अधिवेशन का उद्घाटन करते ऊत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में है अभाविप के पदाधिकारीगण

प्रांतीय अधिवेशन के दौरान प्रदर्शनी का अवलोकन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य अभाविप पदाधिकारी

भीमा कोरेगांव का सच

|प्रा. राजकुमार फुलवारिया|

एक जनवरी 2018 को महाराष्ट् के पुणे जिले के भीमा कोरेगांव की घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी और खींचा। भीमा कोरेगांव में अभिवादन का कार्यक्रम वर्षों से मनाया जाता रहा है, किन्तु इस वर्ष 200 वीं वर्षगांठ में क्या हुआ कि यह अभिवादन कार्यक्रम एक जातीय हिंसा और उपद्रव में तब्दील हो गया। भीमा कोरेगांव की यह हिंसा पुणे, मूंबई और संपूर्ण महाराष्ट्र को जातीयता की आग में झौंक दिया, यह संघर्ष दलित बनाम मराठा और दलित बनाम ब्राह्मण पेशवा आंदोलन का रूप ले लिया। भीमा कोरेगांव की घटना के षड़यंत्र को जानने से पहले हमें भीमा कोरेगांव के युद्ध के इतिहास को जानने की आवश्यकता है।

1757 के प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा बंगाल के नवाब और 1765 में बक्सर की विजय के पश्चात, ईस्ट इंडिया कम्पनी का राजनीतिक शक्ति का विस्तार आरंभ हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक लाख से अधिक भारतीय सैनिकों की फौज तैयार हो गई, लेकिन सेना के अधिकारी अंग्रेज थे। 18 वीं शताब्दी के अंत तक लगभग सभी देशी रियासतों ने अंग्रेज के समक्ष समर्पण कर दिया, अब मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के लिए चुनौती थी, लेकिन द्वितीय अंग्रेज और मराठा युद्ध में मराठा की पराजय से यह चुनौती समाप्त होती दिखाई दी। पेशवा बाजीराव को द्वितीय हार के कारण पुणे पलायन करना पड़ा, किन्तु 1817 के दिसंबर माह में पेशवा ने पुणे को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए लगभग 28,000 की सेना को लेकर कूच किया, जिसकी सूचना मिलते ही शिरूर से करीब 900 सैनिकों की ब्रिटीश सेना की टुकड़ी को कैप्टन फ्रांसिस स्टैटोन के नेतृत्व में पुणे की और कूच करने की आज्ञा मिली, किन्तु पेशवा की सेना और अंग्रेजों की टुकड़ी का सामना पुणे की भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में हो गया और 01 जनवरी 1818 को अंग्रेजों की 900 सैनिकों की टुकड़ी का पेशवा की बड़ी सेना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की इस टुकड़ी ने बड़ी वीरता से लड़ाई लड़ी और पेशवा को आगे बढ़ने से रोक दिया, युद्ध भी किसी निर्णय के बिना समाप्त हो गया। पेशवा भी जनरल

जोसेफ के नेतृत्वु में बड़ी फौज आने की आशंका के पीछे हट गई, ब्रिट्रिश सेना की इस टुकड़ी में, जिसमें 900 सैनिकों में लगभग 500 महार सैनिक थे, उन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा और पेशवा को लौटने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार यह युद्ध भीमा कोरेगांव के युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की और लड़ते हुए 49 सैनिक मारे गये जिसमें 22 सैनिक महार जाति के थे। महार, महाराष्ट्र की प्रमुख जातियों में से एक है, अपने पुणे और स्थानीय महार सैनिकों के शहादत, सम्मान और वीरता के लिए अंग्रेजों ने भीमा कोरगांव में एक विजय स्तम्भ का निर्माण करवाया, विजय स्तम्भ भविष्य में महार परिजनों, महार समाज और महार सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण स्थल बन गया, यह स्तम्भ अंग्रेजों की विजय जश्न के रूप में नहीं था, क्योंकि यह युद्ध बिना किसी निर्णय के समाप्त हुआ, यह विजय स्तम्भ तो महार सैनिकों की वीरता, शौर्य और बलिदान का प्रतीक था, जहां महार परिजन, महार समाज और महार सैनिक प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी को एकत्रित होकर श्रद्धांजलि और अभिवादन कार्यक्रम आयोजित करते थे, किन्तु दुर्भाग्य से 200 वीं वर्षगांठ में कुछ बाहरी तत्त्वों ने इस महार सैनिकों की शौर्य गाथा को जातिगत रंग में रंगने का प्रयास किया, जो युद्ध पेशवा और ईस्ट इंडिया व अंग्रेजों के बीच हुआ उसको महार बनाम मराठा, महार बनाम पेशवा ब्राह्मण के बीच युद्ध बताने का कुत्सित प्रयास किया, जो सत्यता से बिल्कुल उलट है, जहां एक ओर अंग्रेज सेना में महार, राजपूत, मुसलमान आदि सभी जातियों के सैनिक थे, वहीं पेशवा की सेना में भी महार, मंतग, मुसलमान, अफगान, राजपूत और पुर्तगाली सैनिक भी थे। वास्तव

में यह युद्ध औपनिवेशिक शक्ति (ब्रिटिश सेना) बनाम स्थानीय क्षत्रप/रियासतों के बीच युद्ध था जो अंग्रेजी हुकुमत को चुनौती दे रहे थे।

औपनिवेशिक काल में जितने भी युद्ध हुए उनका मूल्यांकन, जाति और धर्म के आधार पर करना न्यायोजित नहीं होगा, अन्यथा 1757 का प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध मुसलमान शासक और ब्रिटिश सेना के बीच हुआ, ब्रिट्रिश सेना में हिन्दु सैनिक अधिक संख्या में थे, इस आधार पर इन युद्धों को मुस्लिम और हिन्दुओं के बीच युद्ध कहेगें?

कुछ तथाकथित विद्वान भीमा कोरेगांव के युद्ध को महार की मुक्ति आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अंग्रेज महार मुक्ति के सहयोगकर्ता, किन्तु 1857 की क्रांति के पश्चात जिन रेजीमेंट को भंग कर दिया गया, उनमें महार रेजीमेंट भी थी, 1892 में बाकायदा अंग्रेज सेना में महारों का प्रवेश निषेध कर दिया गया। निषेध का आधार था कि यह लड़ाकू कौम नहीं है और यह निम्न जाति की है, क्या यही अंग्रेजों द्वारा महार मुक्ति आंदोलन था? 1927 में डा. अम्बेडकर भीमा कोरेगांव गये थे और 1931 में पुणे में महार सम्मेलन में भी इस मांग को बाबा साहेब ने दोहराया कि महारों की ब्रिटिश सेना में प्रतिबंध को समाप्त किया जाये और महारों की सेना में भर्ती आरंभ की जाये।

१२ सितम्बर 1857 को खैबर पख्तुन में सारागढ़ी युद्ध में २१ सिख सैनिकों ने 10,000 से अधिक अफगान सैनिकों के साथ लोहा लिया, ये सिख सैनिक अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे। आज भी इन सैनिकों की वीरता, शौर्य और बलिदान को प्रत्येक भारतीय गर्व करता है, जबकि यह संघर्ष की आजादी के लिए नहीं था, तो क्या इस युद्ध को भी आप सिख बनाम अफगान करार देंगे?

इसी प्रकार 12 सितम्बर 1857 को खैबर पख्तुन में सारागढ़ी युद्ध में 21 सिख सैनिकों ने 10,000 से अधिक अफगान सैनिकों के साथ लोहा लिया, ये सिख सैनिक अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे। आज भी इन सैनिकों की वीरता, शौर्य और बलिदान को प्रत्येक भारतीय गर्व करता है, जबकि यह संघर्ष की आजादी के लिए नहीं था, तो क्या इस युद्ध को भी आप सिख बनाम अफगान करार देंगे? इसी प्रकार 23 सितम्बर 1918 को हाइफा युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों की ओर से लड़ते हुए अदम्य साहस दिखाते हुए हाइफा का युद्ध को जीता तो उस युद्ध को आप, जाति और धर्म के दृष्टिकोण से देखेगें? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग के नरसंहार में जिस अंग्रेज की टुकड़ी ने निहत्थे भारतीय पर गोलियां चलाई, वह टुकड़ी थी गोरखा रेजीमेन्ट की... तथाकथित बुद्धिजीवी इस घटना को भी गोरखा बनाम पंजाबी युद्ध का नाम देंगे? क्या प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में अंग्रेजी सेना की ओर से भारतीय सैनिक विश्व के कोने कोने में जाकर अंग्रेजों की ओर से लड़े और शहीद हुए, आज इंडिया गेट पर लगभग 13,000 से अधिक ऐसे भारतीय सैनिक के नाम अंकित है, क्या हम इनकी वीरता और बलिदान को नकार सकते हैं, जबकि युद्ध बलिदानों में भारत की आजादी का प्रश्न नहीं था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों को प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों द्वारा श्रद्धाजंलि अर्पित की जाती है। औपनिवेशिक काल में सभी युद्धों में भारतीय सैनिकों की शौर्य, वीरता और बलिदान का मूल्यांकन होना चाहिए ना कि जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर!

अब यक्ष प्रश्न यह बनाता है कि वे क्या कारण है कि भीमा कोरेगांव 200 वीं वर्षगांठ में, इस युद्ध को जाति रंग में रग दिया गया, देश में आज भी ब्रिटिश मानसिकता के तथाकथित विद्वान है जो राष्ट्र को भाषा, जाति - सम्प्रदाय, क्षेत्र, वंश (Race) के आधार पर भारत अलग - अलग देखते हैं, जिस प्रकार 1857 की क्रांति के पश्चात भारत राष्ट्र को अंग्रेजों ने बांटने का प्रयास किया, वही मैकाले के मानसपुत्र पुनः भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

आज भारत जाति, भाषा, क्षेत्र की सीमाएं को तोड़कर सशक्त भारत - सक्षम भारत की दिशा में चलने के कारण यह राष्ट्रविरोधी ताकते पुनः संगठित हो रही है, इन राष्ट्रविरोधी ताकतें चाहे वामपंथी, नक्सलवादी या जिहादी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जवाब देना होगा। ■

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के प्राध्यापक हैं।)

विनोबा भावे विश्वविद्यालय में लगातार तीसरी बार अभाविप की जीत

झारखंड के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में शुमार विनोबा भावे विश्वविद्यालय (हजारीबाग) छात्र संघ चुनाव में लगातार तीसरी बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने जीत हासिल की है। विश्वविद्यालय स्तरीय छात्रसंघ चुनाव 2017-18 में अभाविप ने चारों पदों अध्यक्ष पद पर रितेश कुमार यादव, उपाध्यक्ष पद आलोका रानी, सचिव पद आदर्श तरवे और संयुक्त पद पर वर्षा कुमारी ने जीत दर्ज की है। अभाविप उम्मीदवारों के मुकाबले में एनएसयूआई समेत चार छात्र संगठन ने संयुक्त उम्मीदवार उतारा था। विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में कुल चार पद के लिए आठ उम्मीदवार के बीच मुकाबला हुआ। विश्वविद्यालय के परा-स्नातक, विधि महाविद्यालय समेत स्थायी संबंधन महाविद्यालय से जीत कर आये 134 पदाधिकारियों ने मतदान में भाग लिया। कुल 130 मत पड़े, जिसमें 92 पदाधिकारियों ने अभाविप समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किये।

परिणाम से स्पष्ट है कि 10 अन्य छात्र संगठन के प्रतिनिधियों ने भी अभाविप के पक्ष में मतदान किये, चूंकि महाविद्यालयीन छात्र संघ चुनाव के कुल 134 पदों

में से अभाविप ने 82 पर जीत हासिल की थी।जीत पर अभाविप के प्रांत संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह जीत राष्ट्रवादी विचारों के प्रति परिषद् कार्यकर्ताओं के समर्पण को दर्शाता है। विश्वविद्यालय की युवा तरूणाई ने अभाविप के पक्ष में मतदान कर भारत माता के सपनों को साकार रूप प्रदान करने का काम किया है। छात्र संघ चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया कि संकीर्ण राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों को विश्वविद्यालय परिसर में कोई जगह नहीं है। ■

भारत की विरासत है आयुर्वेद : जयराम हाजरा

अभाविप के प्रकल्प जिग्नाशा ने कोलकाता में आयोजित की संगोष्ठी

अभाविप के आयुर्वेद क्षेत्र के आयाम "जिग्नासा" के द्वारा पं. बंग के कोलकाता में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य विरासत में मिले आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिकता को समावेशी के रूप में बनाना एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ाना है। संगोष्ठी का उद्घाटन सुप्रसिद्ध बंगला अभिनेत्री रीता दत्ता, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के निदेशक जयराम हाजरा, सीसीआईएम के वेद विनोद कुमार एवं अभाविप प्रदेश अध्यक्ष रमन कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के जयराम हाजरा ने कहा आयुर्वेद भारत की विरासत है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो पुनः आयुर्वेदिक शिक्षा एवं इलाज की ओर बढ़ना होगा। एलोपेथिक दवाइयां महंगा एवं हानिकारक है। वहीं आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डा. सिसिर कुमार ने कहा कि आयुर्वेद सस्ता एवं लाभकारी है, जबकि डा. असित कुमार गांजा ने कहा कि आयुर्वेदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हाल के दिनों में बढ़ा है। अभाविप का प्रकल्प जिग्नाशा इसमें महत्ती भूमिका अदा कर रही है, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते इसका अपेक्षाकृत प्रसार नहीं हो पायेगा। भारतीय आयुर्वेद की महत्ता को समझें, यह हमे विरासत में मिली है। इसे सहेजकर रखना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। ■

राष्ट्र निर्माण में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की समृद्ध परंपरा का वाहक इसरो

गरीबों से लेकर किसानों, मछुआरों और सूचना के सुपरहाइवे पर दौड़ती नई पीढ़ी समेत देश की सवा अरब से अधिक आबादी के जीवन को भारतीय उपग्रह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हर दिन प्रभावित करते हैं। अब अपनी इस सशक्त एवं किफायती अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जरिये भारत न केवल अंतरिक्ष के बाजार में अपनी जगह बना रहा है, बल्कि इस क्षमता का उपयोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कूटनीतिक अस्त्र के रूप में भी कर रहा है।

। उमाशंकर मिश्र ।

जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए टेलीविजन, बैंकिंग, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, मौसम पूर्वानुमान, स्मार्टफोन, ई-गवर्नेंस, उपग्रह आधारित नेविगेशन जैसे क्षेत्रों में उच्च अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग भारत की प्राथमिकताओं में शीर्ष स्थान पर है। कृत्रिम उपग्रहों और रिमोट सेंसिंग तकनीक वाली भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों के बारे में जानकारियां जुटाने के लिए भी बड़े पैमाने पर हो रहा है।

वास्तव में राष्ट्र निर्माण में अंतरिक्ष को उपकरण के रूप में उपयोग करने की भारत में एक समृद्ध वैज्ञानिक परंपरा है। आज जब भारत 69 वर्षों के गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की उपलब्धियों के प्रकाश-पुंज हर भारतीय के जीवन को छू रहे हैं। अंतरिक्ष में भारत के इस अभियान का आरंभ वर्ष 1969 में अरब सागर के तट पर मछुआरों के एक गांव थुम्बा से हुई थी, जहां वैज्ञानिकों ने भारत के पहले रॉकेट लॉन्च की सुविधा स्थापित करने के लिए एक चर्च के परिसर का इस्तेमाल किया। यह भी कम हैरतअंगेज नहीं है कि उस दौर में साइकिलों पर रॉकेट और बैलगाड़ी पर उपग्रह को लादकर लाया गया था। अंतरिक्ष में भारत की सफलता का परचम आज चांद और मंगल तक पहुंच चुका

है और हम लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के 100वें उपग्रह कार्टोसेट-2 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए जाने के साथ अंतरिक्ष में उड़ान का शतक पूरा करके भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुका है। चेन्नई से 110 किलोमीटर दूर स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से कार्टोसेट-2 समेत 30 अन्य उपग्रह भी इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए हैं।

इसरो के पीएसएलवी-सी40 रॉकेट से भेजे गए इन उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है, जिनमें 710 किलोग्राम वजनी कार्टोसेट-2 सबसे भारी है। जिस प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी40 से इस उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया है, उसकी ऊंचाई 44.4 मीटर और वजन 320 टन है।

कार्टोसेट-2 को पृथ्वी के अवलोकन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये सारे उपग्रह दो अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित किए गए हैं। एक ही यान से अलग-अलग कक्षा में उपग्रह स्थापित करना इसरो की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन उपग्रहों में एक भारतीय माइक्रो सैटेलाइट और एक नैनो सैटेलाइट के अलावा 28 छोटे विदेशी उपग्रह शामिल हैं, जिनका वजन करीब 1,332 किलोग्राम है।

अंतरिक्ष में भेजे गए इन सूक्ष्म एवं अति-सूक्ष्म (नैनो) 28 उपग्रहों में से 19 अमेरिका, पांच दक्षिण कोरिया और एक-एक कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और फिनलैंड के हैं। ये उपग्रह ऐसी तकनीक से लैस हैं, जिनसे किसी निर्धारित स्थल की विशेष तस्वीरें ली जा सकती है। इसीलिए पाकिस्तान और चीन ने इन उपग्रहों को लेकर आपत्ति व्यक्त की है।

उल्लेखनीय है कि इसी श्रृंखला के उपग्रहों से मिली तस्वीरों की मदद से नियंत्रण रेखा पर स्थित पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को नष्ट करने में भारत को सफलता मिली है। इन अंतरराष्ट्रीय उपग्रहों को इसरो और उसकी व्यावसायिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच हुए व्यापारिक समझौतों के तहत लॉन्च किया गया है।

सटीक एवं गुणवत्तापूर्ण तस्वीरें भेजने में सक्षम होने के कारण इसे 'आकाश में आंख' की संज्ञा भी दी जा रही है। सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में यह उपयोगी है क्योंकि दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने में यह उपग्रह उपयोगी हो सकता है। इस उपग्रह द्वारा भेजी गई तस्वीरों का प्रयोग शहरी एवं ग्रामीण अनुप्रयोगों की निगरानी, तटीय भूमि उपयोग और जल वितरण जैसी सेवाओं के प्रबंधन में किया जा सकता है।

इससे पहले पीएसएलवी-39 के जरिये 31 अगस्त, 2017 को इसरो का यह उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम कुछ खामियों के कारण पूरा नहीं हो सका था। मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुसार हीट शील्ड न खुलने के कारण प्रक्षेपण में कठिनाई आयी थी। इस बार वैज्ञानिकों ने उन खामियों को दुरुस्त करके अभियान को पूरा किया है।

कम लागत में किसी अभियान को पूरा करने में भी इसरो ने महारत हासिल कर ली है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष के अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की साख बढ़ी है। केवल 386 करोड़ रुपये में चंद्रयान और फिर मंगलयान 450 करोड़ रुपये में अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजकर इसरो ने दुनिया भर में किफायती प्रक्षेपण की उपलब्धि हासिल की है। यही वजह है कि अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया की सैटेलाइट कंपनियां इसरो पर अधिक भरोसा करती हैं।

इस तरह की खामियों को अंतरिक्ष विज्ञान में आमतौर पर बहुत असामान्य नहीं माना जाता है। अमेरिका समेत विकसित देशों की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों को ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ा है। अच्छी बात यह है कि इसरो गलतियों से सबक लेता रहा है और अन्य देशों के अनुभवों से भी सीख लेकर भारत का यह अग्रणी संस्थान विश्व की अन्य सभी अंतरिक्ष एजेंसियों की अपेक्षा विफलता की दर काफी कम करने में सफल हुआ है। यहां तक कि भारत के चिर प्रतिद्वंद्वी चीन की अंतरिक्ष एजेंसी से भी इसरो की विफलता की दर कम है। विफलता की दर कम होना अंतरिक्ष बाजार में साख का प्रमुख आधार होता है।

इसके अलावा कम लागत में किसी अभियान को पूरा करने में भी इसरो ने महारत हासिल कर ली है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष के अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की साख बढ़ी है। केवल 386 करोड़ रुपये में चंद्रयान और फिर मंगलयान 450 करोड़ रुपये में अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजकर इसरो ने दुनिया भर में किफायती प्रक्षेपण की उपलब्धि हासिल की है। यही वजह है कि अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया की सैटेलाइट कंपनियां इसरो पर अधिक भरोसा करती हैं।

पिछले साल एक साथ 104 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके इसरो ने इतिहास रच दिया था। इससे पूर्व विश्व के किसी एक अंतरिक्ष अभियान में एक साथ इतने उपग्रह नहीं छोड़े गए थे। उच्च कौशल से जुड़ी तकनीक के बिना इस मिशन को पूरा करना असंभव था।

दुनिया में तेजी से बढ़ते उपग्रह प्रक्षेपण के बाजार में इसरो तेजी से पैठ जमा रहा है। लेकिन अंतरिक्ष बाजार का सिरमौर बनने के लिए इसरो को अपनी गति तेज करनी होगी। यह नहीं भूलना होगा कि इस बाजार में कमाई के लिहाज से अमेरिका की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत है। जबकि भारत का हिस्सा करीब चार प्रतिशत ही है। हालांकि, मौजूदा दौर में निजी क्षेत्र का रुझान अंतरिक्ष में बढ़ रहा है, जो इसरो को अंतरराष्ट्रीय मंच पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में तेजी से उभरने का एक प्रमुख अवसर प्रदान कर सकता है। पिछले साल एक साथ सौ से अधिक उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में भेजकर भारत ने इस ओर कदम बढ़ाया है, मगर अभी भी भारी उपग्रह भेजने के मामले में चीन हमसे आगे है।

इसरो का वार्षिक बजट आज नौ हजार करोड़ रुपये है। हालांकि, मानव मिशन को अंजाम देने के लिए यह बजट बेहद कम है। हाल में इसरो के पूर्व चेयरमैन ए.एस. किरण कुमार ने कहा था कि भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम है, पर बजट की कमी आड़े आ रही है। जाहिर है कि हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एवं उनकी लगन में कोई कमी नहीं है।

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां आज उस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं, जहां से अंतरिक्ष कूटनीति की ओर भारत अग्रसर है। पिछले वर्ष अपने सात पड़ोसियों को 450 करोड़ रुपये मूल्य उपग्रह उपहार में देना इसी कूटनीति की बानगी कही जा सकती है। अंतरिक्ष की दुनिया में इससे पहले अंतरिक्ष आधारित संबंधों का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। दक्षिण एशिया के सात देशों के प्रमुखों ने भारत की ओर से दिए गए उपहार की सर्वसम्मति से सराहना की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चहेती परियोजना के तौर पर प्रचारित दक्षिण एशिया उपग्रह (जीसैट-9) अब कक्षा में है। विदेश नीति की इस पहल के जरिये भारत इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का हवाला देते हुए खुद को इस अंतरिक्ष कार्यक्रम से अलग रखा। जबकि सच तो यह है कि उसका यह कार्यक्रम अभी शुरुआती चरण में ही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चहेती परियोजना के तौर पर प्रचारित दक्षिण एशिया उपग्रह (जीसैट-9) अब कक्षा में है। विदेश नीति की इस पहल के जरिये भारत इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का हवाला देते हुए खुद को इस अंतरिक्ष कार्यक्रम से अलग रखा। जबकि सच तो यह है कि उसका यह कार्यक्रम अभी शुरुआती चरण में ही है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमताएं उच्च स्तर की हैं, लेकिन इसरो की क्षमता का सही उपयोग न होने के मामले भी सामने आए हैं। पूर्व में कैग ने इसरो को फटकार लगाई थी कि बड़े रिमोट सेंसिंग उपग्रहों द्वारा अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया?

इसी तरह वर्ष 2004 में प्रक्षेपित किया गया संचार उपग्रह- एडुसैट भी अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सका। इसका उद्देश्य संवादात्मक शिक्षण के जरिए उन लोगों तक पहुंचने का है, जहां आमतौर पर पहुंच नहीं बनाई जा सकती। सैन्य बलों को उपग्रह आधरित अभूतपूर्व मल्टीमीडिया क्षमताएं उपलब्ध कराने के मकसद से वर्ष 2014 में इसरो ने जीसैट-6 को प्रक्षेपित किया था। लेकिन, खबरों की मानें तो इसके लिए जो हैंडसेट जरूरी हैं, जो अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं। इन खामियों की ओर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

अंतरिक्ष में भारत उपलब्धियों को कुछेक खामियों के चलते नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन, एक सवाल यह भी है कि विज्ञान के अन्य क्षेत्रों, जैसे रक्षा तथा चिकित्सा में भारत इसरो जैसी सफलता क्यों अर्जित नहीं कर पा रहा है? उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के मामले में तो हम अमेरिका, रूस और चीन को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन उच्च तकनीकी क्षमता युक्त सैन्य साजो-सामान और परमाणु ऊर्जा जैसी जरूरतों के मामले में हम विदेशों पर आश्रित क्यों हैं? इस पर मंथन करना होगा और समय रहते खामियों को दुरुस्त करके आगे बढ़ना होगा। ■

(लेखक विज्ञान पत्रकार हैं।)

केरल में अभाविप कार्यकर्ता की हत्या

केरल के कन्नूर जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। परिषद् के अनुसार आईटीआई के छात्र श्याम प्रसाद कन्नूर के कूथूपरंबा में अपने मोटरसाईकिल से घर जा रहा था, तभी कार सवार तीन युवकों ने उस पर एकाएक हमला कर दिया। छात्र श्याम किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा लेकिन उन तीनों ने उसका पीछा कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में किसी तरह श्याम को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसने दम तोड़ दी। इस घटना के बाद देश भर में केरल की सत्तासीन वामपंथी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।

अभाविप केरल के प्रदेश मंत्री श्याम राज ने कहा कि वामपंथी राष्ट्रवादी ताकतों की उभार को देखकर घबरा गई है और घिनोनी हरकत पर उतर आई है। हमारे

कार्यकर्ताओं की हत्या राज्य के वामपंथी सरकार के संरक्षण में हो रही है। यह हत्या किसी ओर ने नहीं बल्कि पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) ने कराई है। बता दें कि केरल में राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में अभाविप द्वारा नवबंर 2017 में बहुत बड़ी रैली चलो केरल का आयोजन किया गया था, जिसमें देशभर से 25 हजार से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए थे। ■

युवाओं में देश भक्ति जगाने के लिए अभाविप का अनोखा प्रयोग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, जम्मू - कश्मीर के द्वारा युवाओं में देश भक्ति का भाव विकसित करने के लिए अनोखा अभियान चलाया है। अभाविप के प्रकल्प राष्ट्रीय कला मंच के कलाकारों को साथ लेकर विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं ने जम्मू के विक्रम चौक और गांधीनगर में बिना पूर्व घोषणा के सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। नृत्य, गीत, कलाबाजी, करतब से जुड़े देशभक्ति कार्यक्रम के जरिए युवाओं में देश के प्रति प्रेम विकसित करने की कोशिश की गई। विद्यार्थी परिषद् के महानगर मंत्री पीयूष खजूरिया ने बताया कि रियासत में शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिर रहा है, युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि जम्मू - कश्मीर के युवा विद्यार्थी परिषद् के जुड़कर राष्ट्र के विकास

में भागीदार बने। युवाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना परिषद् का कर्तव्य है। इस मौके पर परिषद् के द्वारा एक 'थीम साँग' भी लॉन्च किया गया। मौके पर विद्यार्थी परिषद् के प्रांत मंत्री वर्षा जड़ियाल समेते परिषद् कार्यकर्ताओं शुभम लंगर महाजन, दीपक, अभिनव, सोनाली, साईराम आदि का सहयोग रहा। ■

Bharat's Foreign Policy: Ambition and Transition

Dr. Abhishek Srivastava

Bharat is becoming an increasingly visible, powerful and influential nation within the global system. It is centred upon her contemporary emergence as a political and economic powerhouse in the Asia. Even before independence, Bharat has maintained semi-autonomous diplomatic relations with few countries, but soon after independence Bharat has joined the Commonwealth of Nations and strongly supported independence movements in other colonies. During the Cold War, Bharat adopted a foreign policy of not aligning itself with any major power bloc. However, Bharat has developed close ties with the Soviet Union and received extensive military support from it. After the end of the Cold War Bharat has diversified her foreign policy and joined many International forum and organisation.

Three and half years ago, Narendra Modi took the oath of office as 14th prime minister of Bharat. Among his first decisions as head of government he invited leaders of all neighbouring countries. It was an unconventional act of diplomacy, While many commentators claimed before his election that Modi would be a nationalist hardliner, a foreign affairs novice, or simply more of the same on external affairs, the prime minister instead proved more active, more pragmatic than many had expected. In his tenure, he has displayed an instinctive understanding of power in the conduct of world affairs, and he has also benefited from being less politically hamstrung than his predecessor Manmohan Singh, with whose worldview he in fact shares much in common.

Prime Minister Narendra Modi's foreign

policy has been characterized by great energy, a desire to break the mold of the past and a penchant for risk-taking. Given the vigour he has imparted, foreign relations should have yielded more significant results. Government of Bharat has prioritized five strategic objectives of Bharat's foreign policy.

1. Prioritizing an integrated neighbourhood; "Neighbourhood First."
2. Leveraging international partnerships to promote Bharat's domestic development.
3. Ensuring a stable and multipolar balance of power in the Indo-Pacific; "Act East."
4. Dissuading Pakistan from supporting terrorism.
5. Advancing Bharat's representation and leadership on matters of global governance.

The Narendra Modi government's pro-active global outreach continued in 2018 with the Prime Minister himself leading the way in World Economic Forum 2018. He energetically reached out to Bharat's partners such as the US and Israel and even to adversaries ally such as China. Bharat also expanded the scope of its engagement with East and Southeast Asia in a year when

Bharat and ASEAN observed 25 years of their Dialogue Partnership, 15 years of summit-level interaction and five years of strategic partnership this year. On the special occasion of 69th republic day Bharat has invited all the ASEAN leaders as a state guest.

The Neighbourhood First policy adopted by the Bharat is meant to indicate four things. The first is New Delhi's willingness to give political and diplomatic priority to its immediate neighbours and the Indian Ocean island states. The second is to provide neighbours with support, as needed, in the form of resources, equipment, and training. The third, and perhaps most important, is greater connectivity and integration, so as to improve the free flow of goods, people, energy, capital, and information. The fourth is to promote a model of Bharat-led regionalism with which its neighbours are comfortable.

Bharat will also continue investing in the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) as an institutional vehicle; it has also expressed a willingness to develop issue-specific groupings that are not held hostage to consensus: a "SAARC minus X" approach. Two examples of this are the Bangladesh-Bhutan-India-Nepal (BBIN) grouping – meant to advance motor vehicle movement, water power management, and inter-grid connectivity – and the common SAARC Satellite which Bharat has decided to proceed with despite Pakistan's objections. These concerted efforts of PM Modi had come up with mixed results. Bangladesh and Bhutan have clearly been positive approach for Bharat.

A second major objective of Bharat's foreign relations has been to leverage international partnerships to advance its domestic development. This includes improving technological access, sourcing capital, adopting best practices, gaining market access, and securing natural resources. In these respects, a truly accurate assessment will only be possible in the years to come, given the lag time between initial agreements and results.

The Narendra Modi government's pro-active global outreach continued in 2018 with the Prime Minister himself leading the way in World Economic Forum 2018. He energetically reached out to Bharat's partners such as the US and Israel and even to adversaries ally such as China. Bharat also expanded the scope of its engagement with East and Southeast Asia in a year when Bharat and ASEAN observed 25 years of their Dialogue Partnership, 15 years of summit-level interaction and five years of strategic partnership this year.

When Modi re-energised two decades long 'Look East' policy with 'Act East,' the purpose was to show greater intent in realising what had long been an aspiration for Bharat. The greater urgency implicit in the shift in terminology is largely an outgrowth of Bharat's concerns regarding China's rise and the upsetting of Asia's delicate balance of power. In addition to the development of military and Chinese infrastructure in Bharat's neighbourhood and the Indian Ocean, Bharat's have three major concerns: the risk of Chinese assertiveness on the disputed border, the possibility of Chinese primacy in the Indo-Pacific region, and an uneven economic playing field.

In terms of the broader strategic context in Asia, Bharat's 'Act East' policy has three distinct facets: institutional, commercial, and security-related. The first has largely been successful mostly as by-product of two decades of economic growth of Bharat. Barring the Asia-Pacific Economic

Cooperation (APEC) forum, Bharat has integrated into Asia's multilateral networks, most notably the apex East Asia Summit. Bharat is trying hard to adapt to the new trade order. Better trade with Southeast Asia will also require developing overland connectivity in northeast part of Bharat, Bangladesh, and Myanmar. Expanding Bharat's port capacities and relaxing constraints on shipping are necessary first steps that are now being taken. But beyond institutional and commercial changes, the greatest departure over the past more then three years has been on the security side.

Bharat and the United States have been able to articulate a Joint Strategic Vision for the Asia-Pacific and Indian Ocean Region, but Bharat has become far less reluctant to embrace "minilateral" or "plurilateral" security arrangements and political consultations. This includes effectively elevating the Malabar naval exercises into a trilateral Bharat-U.S.-Japan initiative, and commencing an official Bharat-Australia-Japan dialogue. Deepening security partnerships with other Indo-Pacific states that share Bharat's concerns remains a priority, but is also largely subject to their own vacillations and political processes.

To date, Act East policy of Bharat has added greater urgency to its earlier aspirations. Certain aspects, such as institutional participation have been more successful over the years, and others such as bilateral and 'minilateral' security cooperation have seen discrete recent improvements. Bharat's primary challenges will lie in preserving the military balance on the disputed border with China, and integrating itself into the region's commercial networks.

After several attempts at setting the terms of engagement over the past few years, Bharat has had to settle upon a two-track policy. The first is to continue keeping lines of engagement open, as long as terrorism tops the agenda and that dialogue is strictly bilateral in nature. This has resulted in a peculiar ping-pong. Inviting Nawaz Sharif to Delhi in 2014 resulted in Pakistan trying to involve the Hurriyat, a coalition of Kashmiri separatists, and Pakistani shelling along the Line of Control with Bharat. The 2015 Ufa Declaration was heavily criticized in Pakistan and led to Islamabad calling off the national security advisor talks under rather farcical circumstances. Modi's Lahore stopover in December 2015 was followed soon after by the Pathankot and Uri attack. The Modi government has not been content with simple bilateral engagement, but has also had to take countermeasures and steps to delegitimize state support for terrorism. New Delhi has welcomed the U.S. decision to stop funding to Pakistan. The greater concern for Bharat is China's decision to go forward with the ambitious, multi-billion dollar China-Pakistan Economic Corridor. While Bharat has expressed its dissent, dissuading Beijing from this path will be a severe challenge; after all, much of China's historical support for Pakistan has been driven by its desire to balance against Bharat.

Bharat is rising in a world system that has been largely favourable to its rise, but one that Bharat was not involved in creating. According to PM Modi, the present international environment represents a rare opportunity for Bharat, which it must use to "position itself in a leading role, rather than just a balancing force, globally." Bharat is not yet fully in a position to lead, or set the rules of the international order, but it is taking steps to seek full membership of the most important global governance platforms.

Bharat is rising in a world system that has been largely favourable to its rise,

While Bharat will continue to lobby consistently for inclusion in multilateral security institutions, its presence in the evolving international economic and trade order will still require a clearer articulation of its trade policy, one that gives greater priority to Bharat's concerns on services, intellectual property, and labour mobility.

but one that Bharat was not involved in creating. According to PM Modi, the present international environment represents a rare opportunity for Bharat, which it must use to "position itself in a leading role, rather than just a balancing force, globally." Bharat is not yet fully in a position to lead, or set the rules of the international order, but it is taking steps to seek full membership of the most important global governance platforms. Bharat is already a member of the G20, the East Asia Summit, and the BRICS coalition, a testament to its status as a large country with a fast-growing economy. New Delhi also naturally aspires for permanent membership on the UN Security Council. It has also been actively lobbying for membership of Nuclear Suppliers Group. These efforts could bear fruit as early as 2018.

A broad overview of the Bharat's foreign policy, particularly over the past years, ought to clearly show not just a strategic vision, but progress along every one of Bharat's major objectives. They include the twin spectres of nationalism and Chinese inroads in Bharat's neighbourhood, insufficient commercial integration with Southeast and East Asia, gaps between diplomatic efforts and agents of domestic implementation, political resistance to engagement with Pakistan, and relative inexperience with leading on matters of global governance. Bharat has to do a better balance and more vigilant in its own neighbourhood, managing or proactively addressing the domestic political fallout of its Pakistan policy, and better coordinating external outcomes with internal development, all the while raising its ambitions and improving its ability to follow through.

After 2014, Bharat has recently embarked upon institution building of its own. The International Solar Alliance represents one such effort, as do the Indian Ocean Rim Association (IORA) and BBIN. While Bharat will continue to lobby consistently for inclusion in multilateral security institutions, its presence in the evolving international economic and trade order will still require a clearer articulation of its trade policy, one that gives greater priority to Bharat's concerns on services, intellectual property, and labour mobility. Bharat has clearly expressed broad comfort with the international order and has actively been lobbying for a seat at the global high table. Learning to lead, however, will be harder. As the prime minister himself has noted, it will require a change in mindsets. ■

(Writer is President of WOSY Delhi & Assistant Professor in PGDAV College, Delhi University)

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का फरवरी 2018 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक भीमा कोरेगांव का सच, भारतीय विदेश नीति, एक राष्ट्र - एक निर्वाचन, इसरो की सफलता, दीनदयाल जी की पुण्यतिथि विषयों पर महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि (11 फरवरी) पर विशेष

विचारक दीनदयाल जी

।संजीव कुमार सिन्हा।

आजादी के बाद भारतीय राजनीति को जिन राजनेताओं ने बौद्धिकता से ओत-प्रोत किया, उनमें पं दीनदयाल उपाध्याय का नाम उल्लेखनीय है। दीनदयाल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उनकी सादगी के लोग कायल थे। वे विनम्रता के प्रतीक थे। सचाई की प्रतिमूर्ति थे। वे कुशल संगठक थे। लेकिन इन सबसे बढ़कर वे प्रखर विचारक थे।

आजादी के तत्काल बाद प्रमुख तौर पर तीन विचारधाराओं का वर्चस्व रहा। कांग्रेस (सेकुलरिज्म), कम्युनिस्ट (साम्यवाद) और सोशलिस्ट पार्टी (समाजवाद)। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वतंत्र भारत में जहां हमें भारतीयता की विचारधारा को अंगीकार कर आगे बढ़ना था वहीं उपरोक्त तीनों ही पार्टियां पाश्चात्य विचारधारा से अनुप्राणित थीं। वे भारतीय विचार से कोसों दूर थीं। राजनीतिक रूप से हम भले ही स्वाधीन हो गए थे लेकिन बौद्धिक रूप से हम पाश्चात्य विचारधारा की जकड़न में थे।

इसी वैचारिक परिवेश को देखते हुए भारतीय विचार से अनुप्राणित एक राजनीतिक दल की आवश्यकता महसूस की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूज्य श्रीगुरूजी से परामर्श कर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 'भारतीय जनसंघ' की स्थापना की। भारतीय जनसंघ की विचारधारा सुनिश्चित करने और उसे प्रभावी संगठन बनाने में पं. दीनदयाल उपाध्याय ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उन्होंने अपने जीवन का क्षण-क्षण लगा दिया। 1952 में कानपुर में जनसंघ का अधिवेशन हुआ। दीनदयाल जी के विचारों से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यदि मुझे दीनदयालजी जैसे चार-पांच लोग मिल जाएं तो मैं पूरे देश में जनसंघ को खड़ा कर लूंगा। उन्होंने दीनदयाल जी को राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व सौंपा। 15 वर्षों तक भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते उन्होंने देश भर में प्रवास कर संगठन

को सशक्त किया और पार्टी की नीति-रीति तय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1967 में वे भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।

25 सितम्बर 1916 को जन्मे दीनदयाल जी मेधावी छात्र थे और सदैव प्रथम श्रेणी में परीक्षाएं उत्तीर्ण होते रहे। उन्होंने सीकर (राजस्थान) से दसवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 1937 में इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी प्राप्त किया और बोर्ड में सर्वप्रथम रहे। 1939 में सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर से प्रथम श्रेणी से बीए किया।

दीनदयाल जी को पढ़ने-लिखने का बहुत शौक था। वे हर वक्त कुछ न कुछ पढ़ते अथवा लिखते दिखाई देते थे। वे खूब प्रवास करते थे, इसलिए रेलगाड़ी में पुस्तकें पढ़ना उनकी आदत थी।

दीनदयाल जी ने पत्रकार की भूमिका का निर्वाह करते हुए भी राष्ट्रवादी आंदोलन को बौद्धिक रूप से प्रखर बनाया। उन्होंने स्वदेश (दैनिक), पांचजन्य (साप्ताहिक) एवं राष्ट्रधर्म (मासिक) पत्रिका के प्रकाशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 'ऑर्गेनाइजर' में लगातार एक साप्ताहिक स्तंभ 'पॉलिटिकल डायरी' लिखते थे, जिससे देश भर में कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलता था।

दीनदयालजी ने साहित्य सृजन भी किया। हिंदी में एक उपन्यास 'सम्राट चंद्रगुप्त' लिखा। बाद में जगद्गुरु

शंकराचार्य की जीवनी लिखी। उन्होंने रा. स्व. संघ के संस्थापक डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार की जीवनी का अनुवाद किया। 'द टू प्लान्स', 'भारतीय अर्थनीतिः विकास की एक दिशा', 'राष्ट्रजीवन की दिशा' उनकी चर्चित कृति हैं।

दीनदयाल जी अन्य राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से भी संपर्क-संवाद करते थे। उन्होंने समाजवादी विचारक डॉ. राममनोहर लोहिया के साथ मिलकर भारत-पाक महासंघ पर संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात को आगे बढ़ाया, जो आज एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में जाना जाता है।

उन दिनों पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद की विचारधारा का बोलबाला था। ऐसे में दीनदयालजी ने भारतीय विचार पर आधारित एकात्म मानववाद का प्रतिपादन किया। खूब विचार-विमर्श के पश्चात् इसका परिष्कार किया। इस पर चर्चा सर्वप्रथम विजयवाड़ा के सम्मेलन में हुई। बाद में ग्वालियर में उन्होंने विचार-विमर्श के लिए सैकड़ों बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया, जिस पर विस्तृत चर्चा हुई। फिर विशाखापत्तनम में एकात्म मानववाद पर प्रस्ताव पारित हुआ। प्रत्येक प्रतिनिधि के एक-एक प्रश्न का समाधान उन्होंने दिया। बौद्धिक जगत में एकात्म मानववाद को बड़ी प्रतिष्ठा मिली। समाजवादी नेता श्री राममनोहर लोहिया ने भी इसकी प्रशंसा की।

एकात्म मानववाद के अनुसार, ''भारतीय संस्कृति व्यक्ति को एक ऐसे संपूर्ण मानव के रूप में स्वीकार करती है जिसकी भौतिक आवश्यकताएं तो हैं परंतु साथ ही उनमें मन, बुद्धि, आत्मा का भी निवास है। जब तक व्यक्ति के इन सब गुणों का समन्वित विकास नहीं होता, तब तक भारतीय संस्कृति के अनुसार व्यक्ति का विकास अपूर्ण है।

व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में चारों का ध्यान रखना होगा। चारों की भूख मिटाए बिना व्यक्ति न तो सुख का अनुभव और न अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की उन्नति आवश्यक है। उपजीविका के साधन शांति, ज्ञान एवं तादात्म्य भाव से ही ये भूखें मिटती हैं। व्यष्टि और समष्टि के बीच का समन्वय भी इस संपूर्णता के विचार से ही संभव है।

संपूर्ण मानव का विचार न कर केवल एक अर्थपरायण मानव को सभी कृतियों का केंद्र बनाकर विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अधूरी है। अधिकतम लाभ की स्वार्थी आकांक्षा इस व्यवस्था की प्रेरक तथा प्रतिस्पर्धा नियामक शक्ति है। ये भाव भारतीय जीवन दर्शन से बेमेल है।

26 से 30 दिसंबर 1967 में कालीकट में भारतीय जनसंघ का अधिवेशन हुआ। जनसंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने बहुत ही विचारशील अध्यक्षीय उद्बोधन दिया था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। आज भी वह भाषण प्रासंगिक है और हर राजनीतिक कार्यकर्ता को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। लेकिन नियति की विडंबना देखिए कि 40 दिन के भीतर 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे यार्ड में उनकी रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हो गई।

भारतीय संस्कृति एकात्मवादी है। सृष्टि की विभिन्न सत्ताओं तथा जीवन के विभिन्न अंगों के दृश्यभेद स्वीकार करते हुए वह उनके अंतर में एकता की खोजकर उनमें समन्वय की स्थापना करती है। परस्पर विरोध और संघर्ष के स्थान पर वह परस्परावलंबन, पूरकता, अनुकूलता और सहयोग के आधार पर सृष्टि की क्रियाओं का विचार करती है। वह एकांगी न होकर सर्वांगीण है। उसका दृष्टिकोण सांप्रदायिक अथवा वर्गवादी न होकर सर्वात्मवादी एवं सर्वोत्कर्षवादी है। एकात्मकता उसकी धुरी है।''

26 से 30 दिसंबर 1967 में कालीकट में भारतीय जनसंघ का अधिवेशन हुआ। जनसंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने बहुत ही विचारशील अध्यक्षीय उद्बोधन दिया था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। आज भी वह भाषण प्रासंगिक है और हर राजनीतिक कार्यकर्ता को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। लेकिन नियति की विडंबना देखिए कि 40 दिन के भीतर 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे यार्ड में उनकी रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हो गई। उनके द्वारा प्रणीत एकात्म मानववाद हम सबके लिए मार्गदर्शन है। हम सभी को उनके विचारों को साकार करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहना चाहिए। ■

अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद प्रकाश नंदा को मिला पद्म भूषण पुरस्कार

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. वेद प्रकाश नंदा को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "पद्म भूषण" से सम्मानित किया गया है। प्रो. नंदा को पद्म भूषण पुरस्कार मिलने से विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। बता दें कि डॉ. नंदा 1951 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय महामंत्री एवं 1956 से 1959 तक लगातार चार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं।

प्रो. वेद प्रकाश नंदा वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, वे 1965 से अमेरिका के प्रसिद्ध डेनेवर विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं बाद में वे डेनवर हॉल्ड विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। अमेरिका के डेन्वेर विश्वविद्यालय में विधि विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक एवं वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके डॉ. वेद प्रकाश नंदा को 2011 में छठा भारतवंशी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। डॉ. नंदा ने अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के बीच भारत की संस्कृति व सभ्यता के प्रचार – प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह विदेश में कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किये जा चुके हैं। डॉ. नंदा लॉ जर्नल व नेशनल मैगजीन का प्रकाशन भी करते हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून पर उनकी 23 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। वह अंतर राष्ट्रीय मुद्दों पर डेन्वेर पोस्ट के नियमित स्तम्भकार हैं। उन्होंने बीबीस व वॉयस ऑफ अमेरिका सहित विश्व के विभिन्न चैनलों पर समीक्षक के नाते भी अपनी विशेष पहचान बनायी है।

डॉ. नंदा को इससे पहले ओरिएंटल फिलॉसॉफी पुरस्कार, विश्व कानूनी विद्वान पुरस्कार, नागरिक अधिकार पुरस्कार, मानवाधिकार और विशेष उपलब्धि पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। वे विश्व न्यायिक संघ के मानव अध्यक्ष, अंतर राष्ट्रीय कानून संघ(अमेरिकन शाखा) के मानद उपाध्यक्ष, अमेरिकी मानव अधिकारी संस्थान की सलाहकार परिषद् के सदस्य रह चुके हैं। ■

सील (SEIL)

अभिनंदन समारोह, मुंबई के दौरान 'सील' प्रतिभागियों को सम्मानित करते विशेष क्षेत्र के संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल व अन्य

दिल्ली में आयोजित 'सील' अभिनंदन समारोह का उद्घटान करते अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सील प्रमुख अतुल कुलकर्णी व अन्य

RNI No.: DELBIL/2017/73636
Date of Posting: 10-11 February, 2018
Date of Publishing: 8 February, 2018

Postal Regd. No.: DL(C)-11/1409/2017-2019
Post Office: NDGPO, New Delhi

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

कराई नसबंदी टेंशन खत्म, ताकत आज भी उतनी, उतना ही दम.

नसबंदी के बाद किसी भी तरह की कमज़ोरी या थकान नहीं होती.
आप अगले दिन से काम पर जा सकते हैं.

जोड़ी ज़िम्मेदार
जो प्लान करे परिवार

इंजेक्शन एम.पी.ए

आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली

गर्भ निरोधक गोलियाँ

कॉपर आई.यू.सी.डी 375 आई.यू.सी.डी 380 A

कंडोम

पुरुष नसबंदी

महिला नसबंदी

परिवार नियोजन के नए और आसान तरीकों की पूरी जानकारी के लिए फ्री कॉल: 1800 116 555
वेब: humdo.nhp.gov.in

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी

आकल्पन : मध्यप्रदेश साधना/2018

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी